Development of Social and Cultural Tourism

9316. SHRI RAM KISHAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to develop social and cultural tourism in the country; and

(b) the details in regard to the religious and cultural pilgrimage centres to be covered in this programme?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) The development of a large number of centres of cultural and religious interest has been undertaken in various Plan peiods. For the development of new centres of cultural interest, the following criteria have been suggested in the Central Tourism Plan 1978—83 :—

(i) the existing and future tourism potential of the place for attracting both international and domestic tourists;

(ii) its accessibility;

(iii) its development in relation to the existing and/or future travel pattern or circuit of tourists within the country;

(iv) its relation to the overall promotional strategy and the development programme of the Department; and

(v) the investment that the State Government concerned would make for developing the infrastructure such as roads, water and electric supply, transport facilities (all these not necessarily charged to the Tourism Sector).

Based on the above criteria, new centers of cultural interest will be selected for development in consultation with the State Governments. In so far as the development of pilgrim centre is concerned, it is proposed to form a Society under the Societies Registration Act of 1860 which will be responsible for the selection of pilgrim centres for releasing funds for the maintenance/improvement/expansion of dharamshalas/sarais/musafarkhanas at these centres.

वित्तीय सहायता के रूप में राज्यों को दिये गये अनुदान

9317. **श्री गंगाभक्त सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वित्तीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को दिये जाने वाले अनुदानों की तुलना में ऋणों के अधिक अनुपात के कारण उन पर ऋण का भार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1977—78 के अन्त तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय सरकार का पृथक-पृथक ऋण भार कितना था ;

(ग) वर्ष 1978—79 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय सरकार को कितनी राशि और उस पर कितना ब्याज अदा किया जायेगा; और

(घ) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से ऋणों के भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति में अभी हाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । राज्यों के ऋणों की रकमों में जो वृद्धि हो रही है वह मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष जो ऋण दिए जाते हैं उनकी रकमें राज्य सरकारों द्वारा की गई वापसी अदायगियों से अधिक होने के परिणामस्वरूप हैं ।

(ख) 1977—78 के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना दी गई है ।